reduced rates of import duty;

(e) what is the present rate of import duty and the reduced rate of import of 30,000 tonnes of VSF;

(f) the amount Government are foregoing on the import of 30.000 tonnes of V.S.F.; and

(g) whether there is any condition on the textile mills importing cotton of long and extra long staple cotton of 5 lakh bales and also 30,000 tonnes of VSF to supply the fine and superfine counts of yarn and also the blended cotton yarn with 10 per cent misture of VSF to handlooms; if so, the counts and quantities of the cotton yarns and cotton blended yarns and at what prices and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) Under the present Import-Export Policy, cotton is permitted to be imported under Open General Licence with zero import duty.

(d) Yes, Sir.

(e) The present rate of import duty of Viscose Staple Fibre (VSF) is 25% ad valorem and the reduced rate of duty for above import quota of 30,000 MT. of VSF is 7%.

(f) Loss of foreign exchange duty to import of V.S.F. at concessional rate of duty is estimated at Rs. 25 crore approximately.

(g) There is no condition as regard cotton. In regard to viscose, it is condition that the importing mill should necessarily use the viscose for blending with cotton. The percentage of cotton and .viscose in blending has not been prescribed. The objective is to augment fibre availability and thereby reduce the pressure on prices of cotton.

नदिया में सूती धागे के मूल्यों में वृद्धि

6578. **श्री विष्णु कान्त शास्त्री** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जनवरी-मार्च, 1994 के दौरान पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में सूती धागे के मूल्य में अस्वाभाविक रूप से वृद्धि हुई और इसके कारण बुनकरों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसके मूल्य में वृद्धि पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में कोई कदम उठाए जाने का विचार है और यदि हां, तो कब तक?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सूती यार्न की कीमतों में अपरिष्कृत कपास तथा अन्य आवकों की कीमतों में वृद्धि हुई है। सरकार ने कपास तथा सूती यार्न की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं:

(1) कपास की 5 लाख गांठों को निशुल्क आयात की मंजूरी दी गई।

(2) 30,000 मी०टन० विस्कोस स्टेपल फाइबर को रियायती शुल्क पर आयात करने की मंजूरी दी गई।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक ने कपास व्यापार का चुनिन्दा ऋण नियंत्रण लगाया है।

(4) कपास के स्टाक पर अधिकतम सीमा लगाने के लिए कपास नियंत्रण आदेश में संशोधन किया है और वस्त्र आयुक्त ने स्टाक का निरीक्षण करना आरंभ कर दिया है।

(5) प्रैसिंग यूनिटों के भंडारण की जांच करने के लिए तथा मानदंडों का पालन करवाने के लिए वस्त्र आयुक्त ने गहन निरीक्षण के आदेश दिए हैं।

(6) अग्रिम लाइसेंस धारकों को निर्देश दिया गया है कि उनको यार्न का निर्यात करने की अनुमति दिए जाने से पहले ही कपास का आयात कर लें।

(7) वस्त्र आयुक्त ने "हैंक यार्न अनिवार्यता आदेश" लागू करना आरंभ कर दिया है।

(8) मिल मालिक औपचारिक तौर पर कम कीमतों पर 10 मिलियन किग्रा० हैंक यार्न सप्लाई करने के लिए सहमत हो गए हैं।

(9) भारतीय कपास निगम द्वारा रखे गए कपास के स्टाक को एनटीसी, एस टी सी तथा सहकारी मिलों को विशेष रूप से हैंक यार्न का उत्पादन करने के लिए रिलीज किया जा रहा है।

(10) 20 मिलियन किलोग्राम हैंक यार्न बाजार दरों से 15 रु० प्रति किलो कम मूल्य पर सहकारी अभिकरणों द्वारा वितरित किया जाएगा।

Subsidies by Development Commissioner, Handlooms

6579. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the details of subsidies given by Development Commissioner, Handlooms to Uttar Pradesh Export Corporation Limited under various heads of Accounts, during the last three years;

(b) whether there are adverse reports against the Corporation for misuse of funds;

(c) whether any enquiry has been made;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKATSWAMY): (a) No subsidy has been given by Development Commissioner for Handlooms during last three years. However financial assistance has been given to Uttar Pradesh Export Corporation Limited during last three years under Market Development Assistance Scheme which may be read as under:—

(Rs. in lakh)

1991-92 to 1993-94	137.07

(b) No such report is available with Government.

(c) Not applicable.

(d) and (e) Do not arise.

Representations for Lifting Cotton Export Restrictions

6580. SYED SIBTEY RAZI: Wffl the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have been requested to lift restrictions on export of cotton;

(b) if so, the details thereof, with background for such requests;

(c) whether Government propose to take action on the requests in the interest of growers of country; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKATSWAMY): (a) to (d) In view of the steep rise in prices of cotton, the Government had temporarily suspended exports of cotton on 9th February, 1994. On 31st March, 1994, the restrictions on exports were removed and export of cotton against contracted quantities, has since been allowed.